भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1556

उत्तर देने की तारीख 4 दिसम्बर, 2024

हाई स्पीड एफटीटीएच इंटरनेट

1556. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बीएसएनएल द्वारा सीधे ग्रामीण और दूरदराज वाले क्षेत्रों के लोगों को किफायती टैरिफ पर लंबी दूरी के कनेक्शन सहित तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारतनेट परियोजना देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान करती है। डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषित पायलट परियोजना के माध्यम से बीएसएनएल ने भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) नामक स्थानीय भागीदारों/उद्यमियों के माध्यम से भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों/गांवों में हाई स्पीड एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 3.8 लाख गांवों को मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के दायरे का विस्तार करने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, एबीपी को ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड एफटीटीएच इंटरनेट के प्रसार में सुधार करने के लिए अनुमोदित किया गया है जिसमें बीएनयू मॉडल का उपयोग करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.5 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन वितरित किए जाने का प्रावधान है।

*****